

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे  
सदस्य

निगरानी प्र.क. 587-दो/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.1.2013 पारित -  
द्वारा- कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ - प्रकरण 51/पुनर्विलोकन/2012-13

1. श्रीमती रामकुंवर पत्नि काशीराम यादव
2. श्रीमती मानकुंवर पत्नि रामस्वरूप यादव
3. श्रीमती शीलकुंवर पत्नि वृजलाल यादव  
ग्राम पचौर पोस्ट पकदारी थाना कुडीला  
खरगापुर जिला टीकमगढ़

—आवेदकगण

विरुद्ध

1. गनपत तनय रमुआ सौर  
निवासीगण ग्राम देरी तहसील बल्देवगढ़  
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2. श्रीमती बैनीवाई पुत्री रमुआ सौर  
ग्राम बन्ने, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़

—अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव  
अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 28.8.2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र.क. 51/2012-13  
पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 3-1-2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू  
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

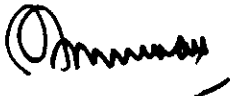
2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र  
कमांक पुअ/टीक/शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21-7-11 लिखकर  
कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया कि श्रीमती परमिया पत्नि डरू  
आदिवासी, केशव तनय डरू आदिवासी, रामेश्वर तनय डरू आदिवासी निवासी  
पूनोलखास थाना दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ का आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ,



जिसमें लिखा है कि उ०प्र०झांसी जिले के सचिन गुप्ता, अमित अग्रवाल ने मेरे पिता डरू तनय हरदास आदिवासी का अहरण कर पिता के नाम की भूमि की रजिस्ट्री कराने का संदेह होने एवं पिता की जमीन की रजिस्ट्री कराकर हत्या की आशंका है। आवेदकों के पिता के नाम प्रतापपुरा ओरछा में मौजा पटैती भूमि सवा तीन एकड़ है जिसके विक्रय करने के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ से विक्रय की मंजूरी ली जाना और मंजूरी के समय बेंचने का अनुबंध कृपाराम यादव से किया जाने का लेख कराया है, जिससे समुचित कार्यवाही की जाकर अमल में लाई जावे। पुलिस अधीक्षक के इस पत्र को आधार मानकर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 51 पुर्नविलोकन/12-13 पंजीबद्ध किया तथा तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-21/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21.5.2010 को स्वमेव निगरानी में सक्षम अनुमति उपरांत लिया तथा अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर आदेश दिनांक 3-1-13 पारित किया एवं तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 21.5.2010 से भूमिस्वामी गनपत सौर की ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एवं 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एवं महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. (आगे इन भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के विक्रय की दी गई अनुमति निरस्त करते हुये आवेदकगण के हित में हुये पंजीकृत विक्रय पत्र के अंतरण को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शून्य कर भूमि पूर्ववत अनावेदकगण के नाम करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थिति रहने के कारण एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि पुलिस



अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र क्रमांक पुअ/टीक/ शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21-7-11 में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विक्रेता अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के हित में गलत ढंग से अथवा अनियमितताओं के आधार पर ग्राम ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एवं 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एवं महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. का विक्रय किया है और जब पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन आवेदकगण एवं अनावेदक से सम्बन्धित नहीं है तथा प्रतापपुरा ओरछा के भूमिस्वामी के संबंध में है - कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना आधार के ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एवं 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एवं महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. के सक्षम अनुमति पर से हुये कय-विक्रय के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करना बेआधार कार्यवाही होना पाई गई है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया गया है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी सौर जाति के होकर अनुसूचित जनजाति संबर्ग से है किन्तु यह भी सही है कि उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 26.12.2007 दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम पचेर उगड़ की भूमि उनके रिहायशी ग्राम से 15 किलो मीटर दूर है जिसके कारण खेती करने में व आने जाने में असुविधा है जिसके कारण इस भूमि से वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है, इसलिये उक्त भूमि को विक्रय करके अन्य ग्रामों में भूमि कय करना चाहते हैं। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विक्रय अनुमति आवेदन की जांच अधीनस्थ अधिकारियों से कराई है नायव तहसीलदार खरगापुर ने हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण किया है तथा मौके की जांच कराई है। जांच कर सन्तुष्टि उपरांत जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.9.2008 में बताया है कि -



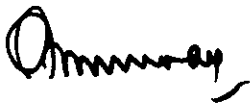
आवेदकगण गनपत एवं बेनीवाई सॉर निवासी देरी को भूमि ख.क. 4/1 एवं 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एवं महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. स्थित ग्राम पंचेर उत्राड़ की भूमि को विक्रय करने की स्वीकृती प्रदान करने हेतु अनुसंशा की जाती है।

नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 15.9.08 से सहमत होकर अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अग्रेषित किया है। नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 17 अ 21/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21.5.10 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है। विचार योग्य बिन्दु है कि जब एक वार अनावेदकगण रिकार्ड्ड भूमिस्वामी को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी गई - आदेश के पालन में भूमि विक्रय हो गई, उसके बाद दिनांक 16-8-2011 को ऐसी कौनसी परिस्थितियां निर्मित हुई, जिनके कारण आदेश दिनांक 21.5.2010 का पुनरावलोकन किया जाना अनिवार्य हुआ ? कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-8-2011 में पुनरावलोकन का आधार यह लिया है -

“ प्रकरण के परीक्षण से पाया गया कि भूमि विक्रय की अनुमति देते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त भूमि किस व्यक्ति को व कितनी कीमत पर हस्तांतरित की जा रही है जिससे यह संभावना बन रही है कि गरीब व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि कम कीमत पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने नाम हस्तांतरित कराई जा सकती है। ”

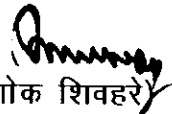
वादग्रस्त भूमि पट्टे की भूमि न होकर विक्रेतागण के भूमिस्वामी स्वत्व पर होना शासकीय अभिलेख में दर्ज है, जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा उपरोक्त आधारों पर प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया गया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा जिन आधारों पर प्रकरण में पुनरावलोकन कार्यवाही पंजीबद्ध की है एवं आदेश पारित किया है वह आधार मिथ्या एवं वास्तविकता के विपरीत हैं।

6/ कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा विक्रय अनुमति हेतु पारित आदेश दि.21.5.10 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के अंतिम पद में इस शर्त पर



कर कंतागण का नामान्तरण किया है। विक्रय पत्र संपादित होने के उपरांत नामान्तरण किये जाने तक किसी भी पक्ष ने विक्रय मूल्य कम प्राप्त होने की शिकायत नहीं की है कंता एवं विक्रेता के मन में बद्धान्ति न होने से कय - विक्रय सद्भाविक पाकर नामान्तरण किया गया है। इन समस्त तथ्यों के होते हुये विक्रय अनुमति आदेश दिनांक 21.5.2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसी आशय के न्यायिक दृष्टांत प्र.क. 557/11/2013 में पारित आदेश दिनांक 21-5-12 में एवं अन्य प्रकरण क्रमांक 588/11/2013 में पारित आदेश दिनांक 16-7-13 में दिये गये हैं, जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/ पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण के नाम की शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रहती है।

  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर